नवभारत 22 मार्च 2026

रविवारीय

तेल रुका तो थम जाएगी तीसरी दुनिया की सांस

डॉ. ब्रह्मदीप अलूने
(विदेशी मामलों के जानकार)

ईरान युद्ध ने विश्व भर में हलचल मचा दी है. फिलीपींस में रेस्तरां बंद हो गए है, बिजली बचाने के लिए फिलीपींस में चार दिन का कार्य सप्ताह अपनाने से लेकर, भारत में रेस्तरां द्वारा गैस की अधिक खपत वाले व्यंजनों को मेनू से हटाने की घटनाएं सामने आ रही है. श्रीलंका में पेट्रोल-डीजल के लिए रात-रात भर लंबी-लंबी कतारें लग रही है. पाकिस्तान में ईद का जश्न फीका पड़ गया है. पाकिस्तान में ऊर्जा संकट राजनीतिक अस्थिरता को और बढ़ा सकता है, जबकि श्रीलंका पहले ही आर्थिक संकट का अनुभव कर चुका है और ऐसे झटकों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है. बांग्लादेश में भी औद्योगिक क्षेत्र और वस्त्र उद्योग, ऊर्जा की कमी से प्रभावित हो गया है.

विकसित देशों के पास सौर, पवन, जल जैसे नवीकरणीय ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा के विकल्प उपलब्ध है, जिससे वे ऊर्जा संकट का सामना अपेक्षाकृत बेहतर तरीके से कर सकते हैं. इन देशों की जनसंख्या भी अपेक्षाकृत कम होती है और ऊर्जा दक्षता अधिक होती है, जिससे दबाव कुछ हद तक कम पड़ता है. विकसित देशों के पास बेहतर तकनीक, मजबूत अर्थव्यवस्था और वैकल्पिक ऊर्जा स्त्रोतों के कारण वे इस संकट को संभालने में अधिक सक्षम हैं. वे जल्दी खुद को परिवर्तित कर सकते है जबकि जीवाश्म ईंधन पर निर्भर गरीब और विकासशील देशों पर इसका असर ज्यादा गहरा और अस्थिरता लाने वाला होगा.

ईरान युद्ध के कारण तेल और गैस की आपूर्ति में आई बाधा का सबसे गहरा असर उन्हीं देशों पर पड़ा है जो या तो आयात पर अत्यधिक निर्भर हैं या आर्थिक रूप से कमजोर हैं. यह संकट केवल ऊर्जा तक सीमित नहीं है, बल्कि व्यापक आर्थिक और सामाजिक अस्थिरता का कारण बन रहा है. भारत और दक्षिण कोरिया जैसे देश ऊर्जा आयात पर निर्भर है. इन देशों की अर्थव्यवस्था औद्योगिक उत्पादन और परिवहन पर आधारित है, जिसके लिए भारी मात्रा में तेल और गैस की आवश्यकता होती है. ईरान युद्ध के कारण खाड़ी क्षेत्र से आपूर्ति बाधित होने पर इन देशों में ईंधन की कीमतें तेजी से बढ़ने का संकट मंडरा रहा है, जिससे महंगाई और उत्पादन लागत दोनों बढ़ सकती है. इसके कारण आर्थिक विकास की गति धीमी पड़ जाएगी है और सरकार पर सब्सिडी तथा वैकल्पिक स्त्रोत खोजने का दबाव बढ़ सकता है. पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश जैसे देश पहले से ही आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं. इनकी ऊर्जा आयात पर निर्भरता अधिक है और विदेशी मुद्रा भंडार सीमित हैं. ऐसे में तेल और गैस की कीमतों में वृद्धि इनके लिए दोहरा संकट पैदा कर सकती है, एक तरफ ऊर्जा की कमी और दूसरी तरफ भुगतान संकट. इन देशों में अक्सर ईंधन की राशनिंग, बिजली कटौती और औद्योगिक उत्पादन में गिरावट देखने को मिलती है. इससे बेरोजगारी बढ़ती है और आम जनता के जीवन स्तर पर सीधा असर पड़ता है.

अमेरिका-इजरायल युद्ध का ईरान पर प्रभाव पूरी दुनिया में महसूस किया जा रहा है. तेहरान ने महत्वपूर्ण होर्मुज जलमार्ग को बंद करके और तेल और गैस से समृद्ध अपने पड़ोसी देशों पर बमबारी करके जवाबी कार्रवाई की है, जिससे ऊर्जा संकट और भी बढ़ गया है. अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने इस स्थिति को वैश्विक तेल बाजार के इतिहास में सबसे बड़ी आपूर्ति व्यवधान बताया है.

> इस प्रकार, यदि तेल और गैस की आपूर्ति लंबे समय तक बाधित रहती है, तो तीसरी दुनिया के देशों में आर्थिक पतन, सामाजिक अव्यवस्था और राजनीतिक अस्थिरता का गंभीर खतरा उत्पन्न हो सकता है. इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते हमले, एक-दूसरे के तेल और ऊर्जा संयंत्रों को निशाना बनाने से वैश्विक स्तर पर अत्यंत गंभीर परिणाम हो सकते है. यदि ईरान खाड़ी क्षेत्र के अन्य देशों के पेट्रोलियम ठिकानों को लगातार निशाना बनता रहा तो यह संघर्ष क्षेत्रीय युद्ध का रूप ले सकता है. खाड़ी क्षेत्र विश्व की ऊर्जा आपूर्ति का प्रमुख केंद्र है और यहां किसी भी प्रकार की बाधा से वैश्विक बाजार में तेल और गैस की भारी कमी हो सकती है. यह संघर्ष ऊर्जा सुरक्षा, भू-राजनीतिक संतुलन और वैश्विक अर्थव्यवस्था को अस्थिर कर सकता है. अत: यह स्थिति केवल क्षेत्रीय नहीं, बल्कि वैश्विक संकट का रूप ले सकती है.

पर्यटकों के लिए सबसे खास जगह माने जाने वाले थाईलैंड में पर्यटकों की संख्या घट गई है, पहले से बुक किए गए कई ग्राहकों ने बुकिंग रद्द कर दी है. पर्यटकों को डर है कि उन्हें घर वापस जाने के लिए कोई उड़ान नहीं मिलेगी. ईरान युद्ध से उत्पन्न तेल और गैस संकट यह स्पष्ट करता है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में ऊर्जा सुरक्षा कितनी महत्वपूर्ण है. जो देश आयात पर निर्भर हैं या आर्थिक रूप से कमजोर हैं वे इस तरह के भू-राजनीतिक संकटों के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील होते हैं. यदि तेल और गैस की आपूर्ति अचानक पूरी तरह बंद हो जाए तो इसका प्रभाव आधुनिक विश्व पर तत्काल और गहरा संकट के रूप में दिखाई देगा. आज की वैश्विक अर्थव्यवस्था और जीवनशैली मूलत: तेल और गैस पर आधारित है इसलिए इनके अभाव में कुछ ही दिनों के भीतर व्यवस्थाएं चरमराने लगेंगी.

सबसे पहले और सबसे स्पष्ट प्रभाव परिवहन क्षेत्र पर पड़ेगा. हवाई यात्रा, समुद्री जहाज, ट्रक परिवहन और निजी वाहन लगभग ठप हो जाएंगे. इससे वैश्विक सप्लाई चेन टूट जाएगी. खाद्यान्न, दवाइयां, ईंधन और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बाधित हो जाएगी, जिससे बाजारों में घबराहट और जमाखोरी शुरू हो सकती है. अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर भी तत्काल असर पड़ेगा और कई देश आवश्यक वस्तुओं के लिए संकट का सामना करेंगे. ऊर्जा क्षेत्र में भी स्थिति गंभीर हो जाएगी. दुनिया के कई हिस्सों में बिजली उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा गैस और तेल पर निर्भर है. इनके बंद होने से पावर प्लांट बंद होने लगेंगे और व्यापक स्तर पर बिजली कटौती या ब्लैकआउट की स्थिति उत्पन्न हो सकती है. आर्थिक दृष्टि से यह स्थिति एक वैश्विक आपदा का रूप ले सकती है. उत्पादन लागत अचानक बढ़ जाएगी, उद्योगों का संचालन रुकने लगेगा और बेरोजगारी तेजी से बढ़ेगी. शेयर बाजारों में भारी गिरावट संभव है और वैश्विक मंदी की स्थिति बन सकती है. विकासशील देशों पर इसका प्रभाव अधिक गंभीर होगा, क्योंकि उनकी अर्थव्यवस्था ऊर्जा आयात पर अधिक निर्भर होती है.

कृषि क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं रहेगा. आधुनिक खेती में ट्रैक्टर, सिंचाई पंप और खाद-उर्वरक के उत्पादन में तेल और गैस की महत्वपूर्ण भूमिका होती है. उर्वरक उद्योग प्राकृतिक गैस पर आधारित है. आपूर्ति रुकने से खाद्यान्न उत्पादन प्रभावित होगा, जिससे खाद्य संकट और भुखमरी की आशंका बढ़ सकती है. ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में जीवन कठिन हो जाएगा. औद्योगिक उत्पादन में भी भारी गिरावट आएगी. प्लास्टिक, रसायन, दवाइयों और अन्य पेट्रोकेमिकल उत्पादों का निर्माण बाधित होगा. कई फैक्ट्रियां बंद हो सकती है, जिससे बड़े पैमाने पर आर्थिक गतिविधियां रुक जाएंगी. इसके साथ ही सामाजिक और राजनीतिक अस्थिरता भी बढ़ सकती है. संसाधनों की कमी से देशों के बीच तनाव और आंतरिक अशांति बढ़ने की संभावना है. अल्पकाल में तेल और गैस की अचानक अनुपस्थिति आधुनिक विश्व के लिए एक गहरे संकट, अव्यवस्था और अनिश्चितता का दौर लेकर आएगी, जो वैश्विक स्तर पर जीवन के हर पहलू को प्रभावित करेगा.

तीसरी दुनिया के अधिकांश देश ऊर्जा के लिए तेल और गैस पर अत्यधिक निर्भर हैं. उनकी अर्थव्यवस्था, परिवहन, कृषि और उद्योग की बुनियाद ही खाड़ी देशों से मिलने वाले तेल और गैस पर टिकी है. यदि इनकी आपूर्ति लंबे समय तक बाधित होती है तो इन देशों के सामने गंभीर अस्तित्वगत संकट खड़ा हो सकता है. गरीब और विकासशील देशों के पास सीमित विदेशी मुद्रा भंडार होता है, जिससे वे महंगे होते तेल और गैस का आयात नहीं कर पाते. इससे मुद्रा का अवमूल्यन, महंगाई और कर्ज संकट तेजी से बढ़ता है. उद्योगों का उत्पादन घटने लगता है, जिससे बेरोजगारी बढ़ती है और आर्थिक विकास रुक जाता है. इसका बड़ा असर ऊर्जा और बुनियादी सेवाओं पर पड़ता है. बिजली उत्पादन, परिवहन और दैनिक जीवन में ऊर्जा की भारी कमी हो जाती है. कई देशों में लंबे समय तक बिजली कटौती, ईंधन की राशनिंग और आवश्यक सेवाओं में बाधा उत्पन्न होती है. कृषि क्षेत्र भी इससे प्रभावित होता है. ट्रैक्टर, सिंचाई और उर्वरक उत्पादन गैस पर निर्भर होते है, जिससे खाद्य संकट की स्थिति बन सकती है. सबसे गंभीर प्रभाव सामाजिक और राजनीतिक अस्थिरता के रूप में सामने आता है. जब महंगाई बढ़ती है और आवश्यक वस्तुओं की कमी होती है तो जनता में असंतोष बढ़ता है, जो विरोध, दंगों और शासन संकट का रूप ले सकता है. कई देशों में यह स्थिति सरकारों के पतन तक पहुंच सकती है.

व्यंग्य

महिला दिवस का इनविटेशन...

रवि उपाध्याय
लेखक व्यंगकार और राजनीतिक समीक्षक हैं)

महिला दिवस तो हर साल आता है. लेकिन इस बार का यह आयोजन हमारे छेदी बाबू के लिए उस समय पेशल बन गया जब उनके नाम एक संस्था द्वारा आयोजित महिला सम्मान समारोह का इनविटेशन पहुंचा. वे इनविटेशन का लिफाफा पा कर आश्चर्य चकित हो गए. उन्होंने इनविटेशन के लिफाफे को चार बार उलट पलट के देखा. उन्हें हर बार लिफाफे पर अपना ही नाम नजर आया. उन्होंने हर बार लिफाफे पर श्रीमान छेदी बाबू ही लिखा पाया. जब उन्हें यह पक्का भरोसा हो गया कि लिफाफे पर लिखा उनका नाम कोई भ्रम नहीं बल्कि हकीक़त है तो उनका दिल भर आया. वे लिफाफे को देख कर बार बार रोमांचित हो रहे थे. उनसे ये ख़ुशी संभाले नहीं संभल रही थी. ऐसा होता भी क्यों नहीं, क्योंकि आज तक किसी ने उन्हें इतनी इज्ज़त नहीं बख्शी थी, जो लिफाफे पर उनके नाम के आगे लिखे श्रीमान शब्द से मिली थी.

ऐसा नहीं है कि इसके पहले छेदी बाबू को कोई लिफाफा मिला ही नहीं हो. वे फ्लैश बैक में पहुंच गए. उन्हें याद आया पहली बार तब लिफाफा मिला था जब वे अपने वेडिंग रिसेप्शन में पर्सनल नववधु के साथ स्टेज पर खड़े हो कर सुरुचि भोज में माल उड़ाने के बाद आए मेहमानों से शुभकामनाएं और गिफ्ट के लिफाफा स्वीकार कर रहे थे. उस समय उनका ध्यान मछली की आंख की तरह गिफ्ट के लिफाफों पर था. बधाई में कौन क्या कह रहा था उनके पल्ले वो कुछ भी नहीं पड़ रहा था. एक तरह से उनकी आँखें खुलीं थीं और कान बंद थे. वे अंगुलियों से टटोल कर लिफाफे की मोटाई देख कर अंदाज लगा रहे थे कि उसका वजन कितना होगा. पास में खड़ी उनकी नववधु कनखियों से देख कर लिफाफों की गिनती लगाती जा रही थीं. उसी समय छेदी बाबू की बड़ी बहन ने भैया से लिफाफे झपट कर अपने बैग में ठूंस लिए. यह देख नई बहू कूड़मुड़ा कर रह गई. फ्लैश बैक से बाहर निकल कर छेदीबाबू एक मुस्कान के साथ वापस वर्तमान में लौट आए. वे इस पशोपेश में पड़ गए कि उनको इनविटेशन क्यों भेजा गया होगा? वे आईने के सामने जा खड़े हुए. उन्होंने मन ही मन कहा लगता तो मैं हंड्रेड पर्सेंट मर्द यानि पुरुष हूँ. फिर इनविटेशन क्या समझ कर भेजा गया होगा. छेदी नाम की वजह से कहीं उन्हें महिला तो नहीं समझ लिया गया हो. क्योंकि वे खुद भी कमलापति को महिला समझने की गलती कर चुके थे. कहीं उनके साथ भी इसी गलतफहमी के चलते मज़ाक तो नहीं किया गया है. छेदी बाबू ने उहापोह के बाद अंततोगत्वा प्रोग्राम में जाने का फैसला कर ही लिया.

अपने मन को समझाते हुए छेदी बाबू को एक दम से ख्याल आया कि यह कहा जाता है कि हर एक पुरूष के अंदर एक बच्चा छुपा होता है. उसी तरह यह भी कहा जाता है कि हर पुरूष में एक आधी नारी भी छुपी होती है. शायद इसीलिए तो महादेव को अर्द्ध नारिश्वर भी कहा जाता है. शायद इसी कारण कुछ पुरुषों में चुगली करने और ईर्ष्या करने का गुण कूट कूट कर भरा होता है. इसका कारण उनमें नारी तत्व की अधिकता हो सकती है. यह सोचते हुए उन्होंने आयोजन में जाने का फैसला किया कि वहां जाने पर थोड़ा चेंज हो जाएगा. वैसे भी कोरोना काल में एक ही चेहरा देख देख कर छेदी बाबू को अपनी और धर्मपत्नी की शक्ल एक सी लगने लगीं थीं. अंतर केवल मूंछों का था. यदि छेदी बाबू के भी मूछें होतीं तो देखने वाले भी चक्कर में पड़ जाते. वे निर्धारित समय पर आयोजन में जा पहुंचे. तब तक वहां बड़ी संख्या में पुरुष दर्शक पहुंच चुके थे. महिलाओं का सज धज कर आने का सिलसिला जारी था. वैसे भी लेडीज़ को सजने संवरने में समय तो लगता ही है. पुरुषों के नसीब में तो इंतजार करना ही होता है. कभी नौकरी का, कभी संतान का, फिर उनकी नौकरी का, अपने घर का, बूढ़ा हो जाने पर अपनों का और आख़िर में बीमार होने पर बुलावे का. अब ज़माना बदल गया है. अब तो मेंस पार्लर में पुरुष भी मसाज, फेशियल, पेडीक्योर और मेनी क्योर करवाने लगे हैं. छेदी बाबू भी दूसरी बार शेविंग करवा कर ही महिला दिवस के आयोजन में पहुंचे थे.

आयोजन स्थल क्रीम और परफ्यूम से महक रहा था. सम्मानित महिलाओं ने अपने संबोधन में जता दिया कि पुरुषों का अस्तित्व उन से ही है. उनके बिना पुरुष का अस्तित्व कुछ भी नहीं है. वो कह रहीं थीं महिलाएं पुरुषों को हर क्षेत्र में टक्कर दे रही हैं. पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं. छेदी बाबू के दिमाग में नीले ड्रम की खबरें घूम गईं. उन्होंने महसूस किया कि आज कल समाज में कितना खुलापन आ गया है. सम्मानित महिलाएं जोश में बोले जा रहीं थीं और मंच से नीचे बैठे पति और पुरुष श्रोता तालियां बजा रहे थे. मंच पर बोल रहीं महिलाएं दर्शकों में बैठे अपने पतियों को तालियां बजाते हुए देख रहीं थीं. एक लेडीज़ ने अपने एड्रेस में कहा कि जहां नारियों की पूजा होती हैं वहां देवता वास करते हैं. इसलिए आप लोग भी खुद को घर में देवता बना कर मिसाल कायम करें. यही हमारी हसरत और शास्त्रों का निर्देश है. छेदी बाबू भी जोर जोर से ताली पीट रहे थे. उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजन शहर शहर और गांव गांव में होना चाहिए. महिलाओं को झांसी की रानी, कामा देवी, दुर्गा भाभी तथा इंदिरा बनना चाहिए.

कार्यक्रम का समापन होने के बाद छेदी बाबू ने तय किया कि वे भी अपने घर में रोज पत्नी की पूजा कर के खुद को देवता साबित कर के ही रहेंगे. चाहे अब कुछ भी हो जाए. वह अब तब तक नहीं रुकेंगे जब उनकी धर्म पत्नी आस पड़ोस में यह न कहने लग जाएं अच्छा बुरा जैसा भी है पर मेरा पति मेरा परमेश्वर है. भला हो सरकार द्वारा लगाए गए उस लॉक डाउन का जिसके चलते छेदी बाबू घर के कामों में एक्सपर्ट हो गए. उन्हें झाडू पोछा बरतनों की साफ सफाई, कपड़े धोने खाना बनाने का तो अनुभव हो ही गया है.

वैश्विक संकट का असर : ईरान-अमेरिका-इजराइल

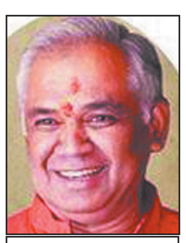

राजीव खंडेलवाल
(लेखक वरिष्ठ कर सलाहकार एवं पूर्व सुधार न्यास अध्यक्ष हैं)

ईरान-अमेरिका-इजराइल युद्ध के कारण खाड़ी क्षेत्र में तेल और गैस आपूर्ति निश्चित रूप से बाधित हुई है. स्ट्रेट ऑफ होर्मुज प्रभावित होने से भारत की एलपीजी आयात पर गंभीर असर पड़ा है. भारत अपनी कुल एलपीजी खपत का लगभग 60% आयात करता है, जिसमें 85-90% मध्य पूर्व से आता है. युद्ध के चलते शिपमेंट्स प्रभावित हुईं, जिससे कीमतों में बढ़ोतरी हुई (दिल्ली में 14.2 किलो घरेलू सिलेंडर की कीमत 7% बढ़कर 913 रुपये हो गई) और कुछ क्षेत्रों में वितरण में देरी की खबरें भी आईं. एटीएफ का बेस प्राइस बढ़ा है. विमानन कंपनियों ने फ्यूल सरचार्ज लगा दिया है.

यद्यपि सरकार ने त्वरित कदम उठाए. पेट्रोलियम मंत्रालय ने 8 मार्च 2026 को एलपीजी कंट्रोल ऑर्डर जारी किया, जिसमें सभी रिफाइनरियों को अधिकतम एलपीजी उत्पादन के निर्देश दिए गए. परिणामस्वरूप घरेलू उत्पादन में 30% से 35% तक की वृद्धि हुई. घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता दी गई, जबकि व्यावसायिक उपयोगकर्ताओं (रेस्तरां, होटल) के लिए पाइप्ड नेचुरल गैस की ओर बदलने की अपील की गई. सरकार ने स्पष्ट कहा घरेलू स्तर पर कोई कमी नहीं है. आपूर्ति वैकल्पिक स्त्रोतों (अमेरिका, नॉर्वे, रूस, कनाडा, अल्जीरिया) से बढ़ाई जा रही है और काला बाजारी-होर्डिंग पर सख्ती से नकेल कसी जा रही है.

> देश के 33 करोड़ से अधिक घरेलू उपभोक्ताओं की रसोई को कोई संकट नहीं पहुंचना चाहिए यह सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है. पैनिक बाइंग रोकने, काला बाजारी पर अंकुश लगाने और वैकल्पिक ऊर्जा (इंडक्शन, पीएनजी) को बढ़ावा देने की जरूरत है. मीडिया को जिम्मेदारी दिखानी चाहिए. तथ्यों पर आधारित रिपोर्टिंग करनी चाहिए. आखिर भाजपा के लाखों कार्यकर्ता आज हैं कहां? वे क्यों नहीं जनता के बीच जाकर समस्या का समाधान निकालने में सहायक हो रहे हैं? सरकार को आपूर्ति श्रृंखला मजबूत करने के साथ-साथ जनता को सही जानकारी देकर भ्रम दूर करना चाहिए. तभी एलपीजी बनाम एलओपी का यह घमासान शांत होगा और देश की प्रगति पर ध्यान केंद्रित रहेगा.

सरकार ने एलपीजी बुकिंग को और पारदर्शी बनाने के लिए ई-केवाईसी (ड्डस्त्रद्धड्डह्य आधारित बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन) को अनिवार्य किया है. पेट्रोलियम मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि यह केवल उन उपभोक्ताओं के लिए है जिन्होंने पहले ई-केवाईसी नहीं किया है. यदि आप पहले कर चुके हैं (गैर-क्क्रूड्ड उपभोक्ता), तो दोबारा नहीं करना है. जिन उपभोक्ताओं का अंतिम रिफिल जून 2025 से पहले का है, उन्हें ई-केवाईसी पूरा करने तक सिलेंडर नहीं मिलेगा. ये उपाय डुप्लिकेट कनेक्शन रोकने, सब्सिडी लीकेज रोकने और ब्लैक मार्केटिंग पर अंकुश लगाने के लिए है. ऑनलाइन बुकिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है, और डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड (क.ब्द्ध कवरेज 53% से बढ़ाकर 72% किया गया है. प्रशासन एवं गैस एजेंसी कंपनियों ने देश के विभिन्न हिस्सों में बड़े पैमाने पर छापेमारी की. 16 मार्च 2026 तक 12,000 से अधिक छापे मारे गए और 15,000 से ज्यादा एलपीजी सिलेंडर जब्त किए गए. दिल्ली, उत्तर प्रदेश, केरल, गोवा, जम्मू-कश्मीर, मध्य प्रदेश आदि राज्यों में प्रमुख कार्रवाई हुई. ये कार्रवाईयां आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत हो रही है, ताकि पैनिक बाइंग और ब्लैक मार्केटिंग रोकी जा सके.

मुख्यधारा का मीडिया जो अब तथाकथित 'गोदी मीडिया' के नाम से जाना जाता है, आश्चर्यजनक रूप से लंबी-चौड़ी लाइनों की तस्वीरें दिखा रहा है. दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, पुणे, बेंगलुरु और गोवा जैसे शहरों में गैस एजेंसियों के बाहर भीड़ दिखाई दे रही है. परंतु सवाल उठता है, यह संकट कितना वास्तविक है? या अफवाहों और पैनिक बाइंग का? सामान्य प्रक्रिया यही है कि जब सिलेंडर खाली होता है, तभी रिफिल कराया जाता है. दो-तीन सिलेंडर रखने वाले उपभोक्ता भी तभी जाते हैं जब जरूरत पड़ती है. इसलिए लंबी लाइनों के बावजूद 'संकट' को अफवाह बताना तथ्यों से अनाचार है. सरकार का सूचना तंत्र लगातार आश्वासन दे रहा है कि निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है. सवाल यह है कि आपूर्ति श्रृंखला टूट कहां रही है? सरकार को स्थानीय वितरण नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट और एजेंटों की भूमिका की जांच करनी चाहिए.

एलपीजी का यह संकट एलओपी के मुद्दों से कहीं बड़ा घमासान मचा रहा है. राहुल गांधी और विपक्ष के अन्य मुद्दे (संसदीय कार्यवाही, बोलने का अधिकार आदि) मीडिया से गायब होकर नैपथत्य मे चले गए हैं. अब संसद में भी एलपीजी मूल्यवृद्धि और आपूर्ति पर ही हंगामा हो रहा है. लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका महत्वपूर्ण है, लेकिन जब वैश्विक संकट (युद्ध के कारण) रसोई तक पहुंच जाता है, तो प्राथमिकता बदल जाती है.

वायरल बीमारियों से लड़ाई में आईसीएमआर-एनआईव्ही की अहम भूमिका

अलप्पुझा केरल से कन्हैया लोधी

देश और प्रदेश ने कोविड का दंश देखा है, इस दंश की भयावहता को करीब से ज्यादातर ने भोगा भी है. कोविड-19 ने जब देश और प्रदेश में पांव पसारना शुरु किया तो शरुआत में ये पता करना कि कौन कोविड जैसे घातक वायरस से प्रभावित है और कौन नहीं. इस बात की पड़ताल करना और जांच करना किसी चुनौती से कम नहीं था. तब देश में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी आईसीएमआर के अधीन काम करने वाले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने खामोशी से ये लड़ाई लड़ी और आखिर में इस पर काबू पाने के साथ ही जनहानि को कम करने में भी बड़ी भूमिका निभाई.

जब केरल प्रवास के दौरान मुझे अलप्पुझा आईसीएमआर की एनआईव्ही की केरल यूनिट में जाने और उसे करीब से देखने का मौका मिला, ये तो किसी सुखद अनुभव से कम नहीं था. हम गर्वित थे कि हमारे देश में इस तरह के संस्थान हैं, जो खामोशी से देश में कोविड जैसे खतरनाक वायरस संक्रमण की जांच के बाद जानकारी समय पर उपलब्ध करा रहे हैं. लेकिन ये मामला यहीं तक सीमित नहीं है. कोविड के अलावा, निपाह, मंकीपॉक्स और इन्फ्लुएंजा जैसे घातक वायरस की जांच और रोकथाम में भी ये इंस्टीट्यूट निर्णायक भूमिका निभा रहा है.

दरअसल केरल देश के उन चुनिंदा राज्यों में शुमार हैं, जहां से सबसे अधिक लोग विदेशों में काम-धंधे के लिए गए हैं. इनमें से ज्यादातर खाड़ी देशों में हैं. खाड़ी देशों के अलावा यूरोप से लेकर अमेरिका, तो दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में भी बड़ी संख्या में अप्रवासियों की संख्या है. जब दुनिया के किसी भी हिस्से में किसी तरह का वायरस संक्रमण होता है तो केरल के कोच्चि के सबसे पहले प्रभावित होने की आशंका बनी रहती है. ये इसलिए कि कोच्चि इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ही केरल के अप्रवासियों की सबसे अधिक आवाजाही बनी रहती है. इसलिए यहां पहुंचने वाले संदिग्ध मरीजों की पहचान कर जांच करना और पुष्टि करने में एनआईव्ही बड़ी भूमिका और जिम्मेदारी निभा रहा है.

3 से अधिक वायरल रोगों की जांच करने में सक्षम है एनआईव्ही- इंडियन इंस्ट्रीट्यूट ऑफ मेडिकल रिसर्च आईसीएमआर के तहत कार्यरत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी एनआईव्ही की केरल यूनिट वायरल बीमारियों की जांच, निगरानी और नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है. यह प्रयोगशाला 30 से अधिक मानव वायरल रोगों की जांच करने में सक्षम है और केरल सहित आसपास के क्षेत्रों के लिए एक प्रमुख रेफरल लैब के रूप में कार्य करती है.

अत्याधुनिक लैब और नई सुविधा- 25 फरवरी 2024 को भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अलप्पुझा के कुरावंथोडु में आईसीएमआर-एनआईव्ही की नई अत्याधुनिक इमारत का उद्घाटन किया. इस केंद्र में बीएसएल -3 प्रयोगशाला, रियल-टाइम आरटी-पीसीआर प्लेटफॉर्म, नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग, नैनोपोर तकनीक और उच्च स्तरीय बायोसेफ्टी सुविधाएं उपलब्ध हैं. इससे क्षेत्र में जैव-चिकित्सा अनुसंधान और सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रतिक्रिया की क्षमता और मजबूत हुई है.

कोविड-19 के दौरान अहम योगदान- कोविड-19 महामारी के दौरान एनआईव्ही की केरल यूनिट राज्य की प्रमुख डायग्नोस्टिक और सर्विलांस प्रयोगशाला के रूप में सामने आई. इस दौरान संस्थान ने कई महत्वपूर्ण कार्य किए, जिनमें शामिल हैं:

- एसएआरएस-वीओव्ही -2 की आरटी-पीसीआर जांच का तेजी से विस्तार
- बड़ी संख्या में सैंपलों की जांच और प्रोसेसिंग
- वायरस के नए वेरिएंट की पहचान के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग
- राज्य की अन्य प्रयोगशालाओं को तकनीकी सहयोग और प्रशिक्षण प्रदान करना
- वायरल प्रकोपों में त्वरित प्रतिक्रिया

यह केंद्र कई बड़े वायरल प्रकोपों के दौरान अग्रिम पंक्ति में रहा है. इनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं:

- निपाह वायरस प्रकोप (2019, 2021 और 2023) संदिग्ध मामलों की आरटी-पीसीआर और इएलआईएसए जांच, फील्ड लैब की स्थापना और राज्य स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वय.
- एमपॉक्स यानी (मंकीपॉक्स) की निगरानी और प्रयोगशाला परीक्षण.
- इन्फ्लुएंजा, आरएसव्ही और एडेनोवायरस जैसे श्वसन वायरस की लगातार निगरानी.

अन्य वायरल रोगों की निगरानी- संस्थान डेंगू, मम्प्स, वेस्ट नाइल वायरस और जापानी एन्सेफलाइटिस जैसे उभरते और पुन: उभरते वायरल संक्रमणों की भी निगरानी करता है. इससे संभावित प्रकोपों का समय रहते पता लगाने और प्रभावी नियंत्रण रणनीतियां तैयार करने में मदद मिलती है.

टीबी उन्मूलन के लिए विशेष अभियान- आईसीएमआर-एनआईव्ही ने अलप्पुझा जिले में एसीसीइएनडी टीबी नामक परियोजना भी लागू की. इस अभियान के तहत:

- लगभग 2.6 लाख लोगों की स्क्रीनिंग की गई.
- 848 एक्स-रे और 673 मॉलिक्यूलर जांच की गईं.
- 11 टीबी मरीजों की पहचान कर उनका इलाज शुरू किया गया.

वेक्टर जनित रोग नियंत्रण में समुदाय की भागीदारी- संस्थान ने अलप्पुझा नगरपालिका में डेंगू और चिकनगुनिया जैसे वेक्टर जनित रोगों को रोकने के लिए समुदाय आधारित कार्यक्रम भी चलाया. इस पहल में घर-घर जागरूकता अभियान, मच्छरों के प्रजनन स्थलों की निगरानी, प्लास्टिक कचरा प्रबंधन और पर्यावरण अनुकूल लार्वा नियंत्रण जैसे कदम शामिल थे.

गुणवत्ता और अंतरराष्ट्रीय मान्यता- यह प्रयोगशाला डब्ल्यूएचओ मिजल्स-रूबैला लेबोरेटरी नेटवर्क का हिस्सा है और राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता परीक्षण कार्यक्रमों में भाग लेकर उच्च स्तर की जांच और विश्वसनीय रिपोर्टिंग सुनिश्चित करती है.

कुल मिलाकर, आईसीएमआर-एनआईव्ही की केरल यूनिट राज्य में वायरल बीमारियों की समय पर पहचान, निगरानी और नियंत्रण में अहम भूमिका निभा रही है, जिससे भविष्य में संभावित महामारी और संक्रमणों से निपटने की तैयारी और मजबूत हो रही है.